

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र. (पर्यावरण, वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)



पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी भोपाल–462016 (म.प्र.) बेवसाईट–<u>http://www.mpseiaa.nic.in</u> दूरभाषनं. – 0755–2466970, 2466859

फैक्सनं. – 0755–2462136

No:450 / SEIAA/2025 Date: 24/05/2025

प्रति,

M/s. Dev Associates,

Partner Shri Keshav Mangal, R/o Saroj Traders, Sadar Bazar, District-Shivpuri (MP)-473551 E-mail - devassociate639@gmail.com

विषय :- Proposal No. SIA/MP/MIN/518419/2025- Case No 10871/2023 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method) in an area of 4.00 ha. for production capacity of 10000 cum per year, Khasra No. 228/1, Village-Devri, Tehsil-Narwar, District-Shivpuri (MP) by M/s. Dev Associates, Partner Shri Keshav Mangal, R/o Saroj Traders, Sadar Bazar, District-Shivpuri (MP)-473551.

विषयान्तर्गत प्रकरण में राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) द्वारा 770वीं बैठक दिनांक 11.02.2025 में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित पर्यावरण अनुमति प्रदान किये जाने की अनुशंसा कर प्रकरण दिनांक 19.02.2025 को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) को अग्रेषित किया गया। प्रश्नाधीन प्रकरण SEIAA की बैठक में विचारण नहीं होने के कारण 45 दिवस से अधिक की अवधि समाप्त हो गई है।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की ईआईए अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के पैरा 8 की कंडिका (iii) इस प्रकार है - ''In the event that the decision of the regulatory authority is not communicated to the applicant within the period specified in subparagraphs (i) or (ii) above, as applicable, the applicant may proceed as if the environment clearance sought for has been granted or denied by the regulatory authority in terms of the final recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned.''

अतः ईआईए अधिसूचना के पैरा 8 की कंडिका (iii) के अनुसार उक्त प्रकरण में SEAC की 770वीं बैठक दिनांक 11.02.2025 में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित पर्यावरण स्वीकृति हेतु की गई अनुशंसा को अंतिम निर्णय मानते हुए राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा "Deemed Approval" माना जाकर पर्यावरण अनुमति दी जाती है। तद्नुसार प्रकरण में ईआईए अधिसूचना के पैरा 8 की कंडिका (iii) के अनुसार आगामी आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करने हेतु आप स्वतंत्र हैं।

(प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग द्वारा अनुमोदित)

(श्रीमन

कार्यपालन संचालक, एप्को एवं सदस्य सचिव, SEIAA

पु. क. 451 /SEIAA/2025 भोपाल दिनांक - 24/05/2025

प्रतिलिपि:-

- 1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- संयुक्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोइ, नई दिल्ली - 110003।
- 3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय म.प्र. शासन, मंत्रालय भोपाल (म.प्र.)।
- 4. अध्यक्ष, SEIAA, एप्को पर्यावरण परिसर भोपाल (म.प्र.)।
- 5. अध्यक्ष SEAC, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5 अरेरा कॉलोनी भोपाल (म.प्र.)।
- सदस्य सचिव, SEAC एवं सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5 अरेरा कॉलोनी भोपाल।
- 7. कलेक्टर, जिला शिवप्री (म.प्र.)।
- 8. वन मंडलाधिकारी, जिला शिवपुरी (म.प्र.)।
- 9. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल।
- 10. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल 462002।
- 11. खनिज अधिकारी, जिला शिवप्री (म.प्र.)।

12. संबंधित फाईल।

की ओर सूचनार्थ।

कार्यपालन संचालक, एप्को एवं सदस्य सचिव, SEIAA

STATE EXPERT APPRAISAL COMMITTEEMINUTES OF 11thFebruary, 2025 770thMEETING

10. Case No 10871/2023 Shri Keshav Mangal, Partner, M/s. Dev Associates, R/o Saroj Traders, Sadar Bazar, District-Shivpuri (MP)-473551, Prior Environment Clearance for Devri Khurd Stone Quarry in an area of 4.00 ha. (10000 cum per year) (Khasra No. 228/1), Village-Devri, Tehsil-Narwar, District-Shivpuri (MP) (TOR) Case no. 518419

Earliear this case was discussed in the ToR Recommended 714th SEAC Meeting dt.18/01/202PP submitted following details on Praivesh portal 2.0

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का	देव एसोसियेट, पार्टनर श्री केशव मंगल, निवासी– देव	
नाम व पता	एसोसियेट द्वारा सरोज ट्रेडर्स सदर बाजार, शिवपुरी (म.प्र)	
खसरा नं. / क्षेत्रफल	खसरा नंबर —228 / 1, 4.00 हैक्टेयर	
(सरकारी ⁄ निजी)	(शासकीय भूमि –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	
स्थल	ग्राम– देवरीखुर्द तहसील–नरवर, जिला– शिवपुरी	
लीज स्वीकृति	संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल	
	द्वारा पत्र क्रमांक 16189 ⁄ न.क.—40 ⁄ 2022 भोपाल दिनांक	
	25 / 11 / 2022 के द्वारा 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत	
	किया गया है।	
अनुमोदित खनन् योजना	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।	
अनुसार ब्लास्टिंग / रॉक		
ब्रेकर का उल्लेख करें।		
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट	
डिया ई.सी. का विवरण	नया प्रोजेक्ट	
(यदि लागू हो)		
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सेक की714 वीं बैठक दिनांक18.01.2024 को अनुशंसित, सिया	
	के पत्र क्रमांक 3167 / SEIAA / 2024 दिनांक 01.03.2024 के	
	द्वारा उत्पादन क्षमता 10,000 घनमीटर⁄वर्ष एम–सैंड के लिए	
	टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक	
	द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है।	
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्पादन क्षमता १०,००० घनमीटर / वर्ष	
	एम–सैंड हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन्	
	योजना अनुसार उत्पादन क्षमता 10,000 घनमीटर⁄वर्ष एम–सैंड	
	है।	
500 मीटर की परिधि में	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल	

STATE EXPERT APPRAISAL COMMITTEEMINUTESOF11th February, 2025770th MEETING00

अन्य खदानें	प्रमाण—पत्र क्रमांक 1260/3—6/खनि/89/21/2023 दिनांक 25/10/2023अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02अन्य खदानें
	\sim
	संचालित / स्वीकृत है, इस प्रकार इस खदान को मिलाकर कुल
	रकबा 12.00हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1श्रेणी का है।
वनमण्डलाधिकारी की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल
अनापत्ति	प्रमाण–पत्र कमांक 1260/3–6/खनि/89/21/2023 दिनांक
	25 / 10 / 2023अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल
	पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित
	नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल
	प्रमाण–पत्र क्रमांक 1260/3–6/खनि/89/21/2023 दिनांक
	25 / 10 / 2023अनुसार 500 मीटर की परिधि में शमशान घाट
	200 मीटर,रेलवे लाइन , नदी , रोड़ की दूरी 100मी. से अधिक
	शेष मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व
	धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक,सार्वजनिक भवन⁄राष्ट्रीय
	राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन,
	हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं/तालाब/बांध/स्टॉपडैम/
	रास्ता नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम	ग्राम पंचायत देवरीखुर्दके ठेहराव प्रस्ताव क्रिमांक 05 दिनांक 14.
पंचायत की अनापत्ति	04.2021 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से ग्राम
	पंचायत बिलावलीको कोई आपत्ति नहीं है ।
क्रेशर की स्थिति (लीज	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं हैं।
के बाहर या लीज क्षेत्र	
के अन्दर)	
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में स्थित पेड़ो का विवरण— 00
प्रस्तावित स्थल की	 पूर्व दिशा – पूर्व दिशा में 78 मी. पर नहर स्थित हैं
गूगल इमेज अनुसार	तथानिकटतम संवेदनशीलता ध्यान में रखते हुए नहर से 200
वर्तमान स्थिति	मी. का सेट बैक प्रस्तावित किया गया है, नहर से खनन क्षेत्र
	200 मीटर तक कोई खनन कार्य नहीं किया जावेगा।

STATE EXPERT APPRAISAL COMMITTEEMINUTES OF 11thFebruary, 2025 770thMEETING

	पश्चिम दिशा –पश्चिम दिशा में 123 मी. पर नहर स्थित हैं तथानिकटतम संवेदनशीलता ध्यान में रखते हुए नहर से 200 मी. का सेट बैक प्रस्तावित किया गया है, नहर से खनन क्षेत्र 200 मीटर तक कोई खनन कार्य नहीं किया जावेगा।
जन सुनवाई	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 31/08/2024 को संपन्न हुई रोजगार दिया जाये पानी का छिड़काव किया जाये,वृक्षारोपण का प्रबंध किया जाये मरम्मत कार्य किया जाये ,सिलाई सेंटर खोले जाये,स्कूल की पुताई करवाई जाये,हैंडपंप की व्यवस्था की जाये, बच्चों के स्कूल में पंखे की व्यवस्था की जाये,स्कूल में बच्चों के लिए खेल कूद के सामान उपलब्ध कराये जाये. उपरोक्त आपत्तियॉ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना/सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के पत्र क्रमांक 1258 / 3.6 / खनिज / 89 / 21 / 2023 दिनांक 25 / 10 / 2023अनुसार उक्त उत्खनि पट्टा में सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो जाने उपरांत आगामी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल कर लिया जाएगा।

The case presented by the Environmental Consultant Shri Ram Raghav, FAE, Ms. Green Circle, INC, Vadodara long with PP Shri Pushparaj Patel.

After deliberations and the submissions and presentation made by the PP were found to be satisfactory and acceptable hence, the case is recommended for grant of Prior Environment Clearance for Devri Khurd Stone Quarry in an area of 4.00 ha. (10000 cum per year) (Khasra No. 228/1), Village-Devri, Tehsil-Narwar, District-Shivpuri (MP) With Standard and following specific conditions with Annexure "A":

- पूर्व दिशा में 78 मी. पर नहर स्थित हैं एवं पश्चिम दिशा में 123 मी. पर नहर स्थित है । अतः नियमानुसार 200 मीटर सेडबैक छोड़ते हुये खनन कार्य किया जावे ।
- अनुमोदित खनन् योजना अनुसार उत्पादन क्षमता–उत्पादन क्षमता 10,000 घनमीटर⁄वर्ष एम–सैंड।

STATE EXPERT APPRAISAL COMMITTEEMINUTES OF 11thFebruary, 2025 770thMEETING

- पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 16.705 लाख एवं रिकरिंग राशि रू.3.38 लाख प्रति वर्ष।
- वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपणकिये जाये
- सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.80 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 06 माह में पूर्ण किये जाये :--

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू.में)
 ग्राम में स्थित शासकीय स्कूल में पंखे, बच्चों के लिए खेल कूद के सामान, स्कूल में पेंटिंग / पुताई करवाए जाने का प्रावधान है ग्राम पंचायत देवरी खुर्द के अन्दर ग्राम देवरी खुर्द में आंगनवाडी में 	₹10,000/-
पंखा एवं मरम्मत और पुताई करवाए जाने का प्रावधान है एवं आंगनवाडी में पीने के पानी के लिए टंकी भी रखवाई जावेगी • हैंडपंप की व्यवस्था के लिए ग्राम पंचायत के माध्यम से सहयोग राशि	₹15,000/-
भूप्रवेश के उपरांत पंचायत को उपलब्ध करवाया जावेगा • गाँव के लोगो के लिए रोजगार हेतु सिलाई सेंटर खोले जाने के लिए ग्राम पंचायत में सहयोग राशि प्रदान की जावेगी	₹50,000/-
	₹25,000/-
कुल	1,00,000/-

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 जून 2024

<u>Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific</u> <u>conditions and cases appraised for grant of TOR:</u>

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

- 1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
- 2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- 3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
- 4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
- 5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
- 6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
- 7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
- 8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
- 9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
- 10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
- 11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
- 12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
- 13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
- 14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
- 15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
- 16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
- 17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
- 18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 जून 2024

- 19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
- 20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
- 21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
- 22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
- 23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
- 24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
- 25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora, fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
- 26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
- 27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
- 28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
- 29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
 - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
 - f. Plantation and CER activities.
- 30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
- 32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland

764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 जून 2024

and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.

- 34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
- 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
- 36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

- 1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
- 2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- 3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
- 4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
- 5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
- 6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
- 7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on upstream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
- 8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be $1/4^{\text{th}}$ or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
- 9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
- 10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
- 11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
- 12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
- 13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
- 14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.